

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4572 का उत्तर

छत्तीसगढ़ के बस्तर में रेल परियोजनाएँ

4572. श्री महेश कश्यप:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रही रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और
- (ग) इन परियोजनाओं की कार्य प्रगति रिपोर्ट क्या है और उपरोक्त परियोजनाओं में प्रयुक्त की जा रही प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए, निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1.	जगदलपुर-किरनदुल दोहरीकरण (150 कि.मी.)	1500
2.	जगदलपुर-रावधाट नई लाइन (140 कि.मी.)	3513

इस परियोजना के 150 किलोमीटर में से 128 किलोमीटर का कार्य पूरा किया जा चुका है और शेष 22 किलोमीटर पर कार्य शुरू किया गया है।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्य शुरू किए गए हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)
1	कोठागुड़ेम-किरंदुल नई लाइन	180
2	बीजापुर के रास्ते गढ़चिरौली से बचेली नई लाइन	490

छत्तीसगढ़:

हाल ही के वर्षों में बजट आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-2014	₹311 करोड़ प्रति वर्ष
2025-2026	₹6925 करोड़ (22 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और वर्ष 2014-24 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई
2009-14	32 कि.मी.	6.4 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-25	1189 कि.मी.	108.1 कि.मी. प्रति वर्ष (16 गुना से अधिक)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 31,619 करोड़ रुपए लागत की 1,931 कि.मी. कुल लंबाई की 26 परियोजनाएं (06 नई लाइन और 20 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से

1023 कि.मी. लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2025 तक 16,325 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इस कार्य की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण की कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2025 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	6	609	184	6154
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	20	1323	839	10171
कुल	26	1931	1023	16325

छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम लागत (करोड़ रु. में)
1	खरसिया-कोरिछापर नई लाइन (43 कि.मी.)	851
2	सलका रोड-खोंगसरा - कहीं-कहीं दोहरीकरण (26 कि.मी.)	181
3	दुर्ग-राजनांदगांव दोहरीकरण (31 कि.मी.)	250
4	बिलासपुर में फ्लाईओवर सहित खोदरी-अनूपपुर दोहरीकरण (72 कि.मी.)	792
5	रायपुर - टिटलागढ़ दोहरीकरण (203 कि.मी.)	1171
6	बिलासपुर-उरकुरा तीसरी लाइन (110 कि.मी.)	365
7	चंपा-झारसुगुड़ा तीसरी लाइन (152 कि.मी.)	1227
8	पेंड्रा रोड-अनूपपुर तीसरी लाइन (50 कि.मी.)	394

पिछले 5 वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली ₹14,943 करोड़ की लागत की 676 किलोमीटर लंबाई की 19 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

छत्तीसगढ़ में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएँ, जो शुरू की गई हैं, वे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल लागत (करोड़)
1	दल्लीराजहरा-रावधाट नई लाइन (95 किलोमीटर)	1627
2	रावधाट-जगदलपुर नई लाइन (140 किलोमीटर)	3513
3	खरसिया-धरमजयगढ़ नई लाइन (122 किलोमीटर)	3438
4	गेवरा रोड-पेंड्रा रोड नई लाइन (135 किलोमीटर)	3724
5	धरमजयगढ़-कोरबा नई लाइन (63 किलोमीटर)	1686
6	सरडेगा-भालुमुंडा नई लाइन (37 किलोमीटर)	1282
7	किरंदुल-जदगलपुर दोहरीकरण (150 किलोमीटर)	1500
8	जगदलपुर-कोरापुट दोहरीकरण (107 किलोमीटर)	1547
9	झारसुगुड़ा-बिलासपुर -चौथी लाइन (206 किलोमीटर)	2596
10	राजनांदगांव-नागपुर तीसरी लाइन (228 किलोमीटर)	3545
11	बोरीडांड-अम्बिकापुर दोहरीकरण (80 किलोमीटर)	1243
12	राजनांदगांव-डॉंगरगढ़ चौथी लाइन (31 किलोमीटर)	328
13	भाटापारा- हथबंध चौथी लाइन (16 किलोमीटर)	177
14	खरसिया-परमालकसा 5वीं और 6वीं लाइन (278 किलोमीटर)	7854

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले कुल 5657 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाले 60 सर्वेक्षण कार्य (26 नई लाइन और 34 दोहरीकरण) शुरू किए गए हैं।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में संपर्कता में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य शुरू किए गए हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)
1	सरडेगा-अंबिकापुर नई लाइन	218
2	कोठागुडेम-किरंदुल नई लाइन	180
3	गढ़चिरौली से बचेली वाया बीजापुर नई लाइन	490
4	अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन	285
5	बैकुंठ-उरकुरा चौथी लाइन	26
6	पेंड्रा रोड-शहडोल चौथी लाइन	85
7	डोंगरगढ़-गोंदिया चौथी लाइन	73
8	बिलासपुर-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन	103
9	चांपा-गेवरा रोड तीसरी और चौथी लाइन	92

भारतीय रेल क्षेत्रीय रेलों के जरिए परिचालन, अनुरक्षण और विस्तारण करती है। अतः, रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्र-वार किया जाता है न कि राज्य-वार/संघ शासित/क्षेत्र-वार/जिले-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएँ राज्य/संघ शासित क्षेत्र/जिले की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

किसी भी रेल परियोजनाओं की स्वीकृति विभिन्न मापदंडों/कारकों पर निर्भर करती हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- प्रस्तावित मार्ग का प्रत्याशित यातायात अनुमान और लाभप्रदता।
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई प्रथम और अंतिम छोर संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई माँगें,
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधि की समग्र उपलब्धता

छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल परियोजनाएँ भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व तट रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं।

रेल परियोजनाओं का लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

किसी भी रेल परियोजना/ओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी साधनों की स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
